आज़ादी का
अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 19.02.2023 से 25.02.2023)

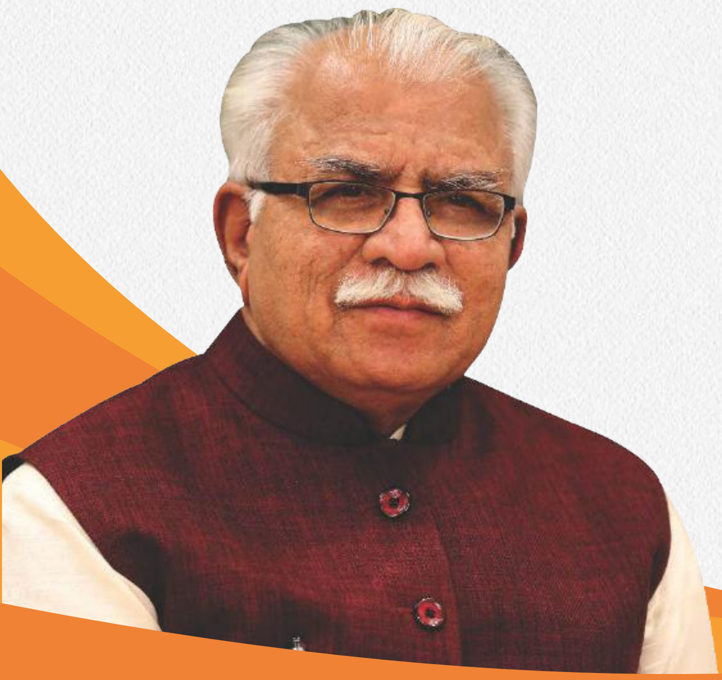

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

साप्ताहिक सूचना पत्र

हरियाणवी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिकन के अध्यक्ष श्री राजेश वशिष्ठ से शिष्टाचार भेंट

(दिनांक 19.02.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास पर हरियाणवी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिकन के अध्यक्ष श्री राजेश वशिष्ठ ने शिष्टाचार भेंट की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट का गठन किया है ताकि विदेश में जाकर शिक्षा व रोजगार के इच्छुक छात्रों को सहज सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि हरियाणवी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिकन फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट से सहयोग करे, आपसी तालमेल बनाए और विदेशों में शिक्षा व रोजगार के लिए जाने वाले बच्चों का मार्गदर्शन भी करे। श्री वशिष्ठ ने माननीय मुख्यमंत्री जी का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती के आयोजन के लिए धन्यवाद किया और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को कनाडा में आने का निमंत्रण भी दिया।

मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल

(दिनांक 19.02.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जीवन में सादगी की एक और मिसाल प्रस्तुत करते हुए अपने विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा सम्मान स्वरूप भेंट किए गए उपहारों को नीलाम करने का निर्णय लिया है। मानीनय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने जीवन में मिले उपहारों की नीलामी पोर्टल के माध्यम से की है। इससे मिली धनराशि को 'नमामि गंगे सफाई अभियान' में लगाया। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए उपहारों से प्राप्त धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रयोग में लाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों ऑनलाईन पोर्टल https://cmuphaarhry.com की शुरूआत हो गई है। यह पोर्टल 28 फरवरी, 2023 तक खुला रहेगा। उसके बाद साल में तीन या चार बार पोर्टल को चरणबद्ध तरीके से दोबारा खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 51 उपहारों की नीलामी

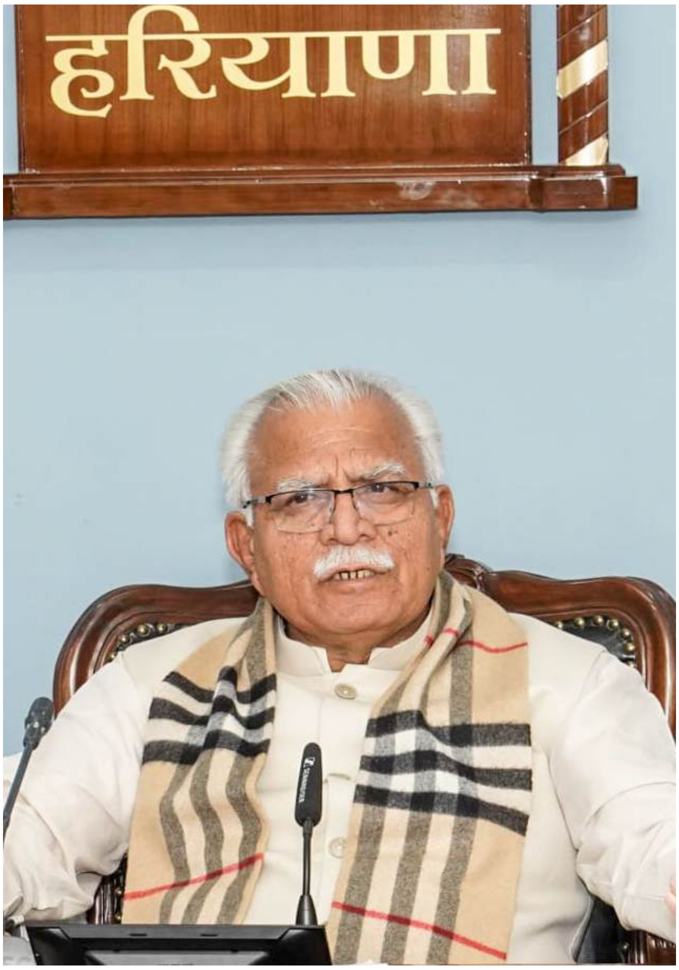

की जाएगी। आमजन इस पोर्टल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को मिले उपहार खरीद सकते हैं। इससे मिलने वाली राशि को हरियाणा के लोगो की भलाई और जनहितेशी कार्यों में लगाया जाएगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

पंचकूला सेक्टर–14 स्थित निदेशालय ईएसआई स्वास्थ्य संरक्षण विभाग भवन का उद्घाटन

(दिनांक 19.02.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने आज सेक्टर–14 स्थित निदेशालय ईएसआई स्वास्थ्य संरक्षण विभाग हरियाणा के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस भवन के बनने से हरियाणा के साथ साथ उत्तर क्षेत्र के बीमित व्यक्तियों को बेहतर प्रशासनिक सुविधायें उपलब्ध होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने ईएसआई डिस्पेंसरी राई और बरही सोनीपत का शिलान्यास भी किया। वर्तमान में हरियाणा में ईएसआई बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या 25 लाख है।

भवन के उद्घाटन उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पंचकूला में ईएसआई के नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यालय के शुरू होने से हरियाणा के साथ साथ पंजाब, हिमाचल आदि प्रदेशों के ईएसआई के बीमित व्यक्तियों की प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाया जा सकेगा। उन्होनें कहा कि प्रदेश में ईएसआई के माध्यम से लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही है और हरियाणा में इस क्षेत्र में बेहतर कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। निरोगी हरियाणा योजना के तहत हरियाणा के सभी नागरिकों की दो साल में एक बार स्वास्थ्य जांच करने की शुरुआत की गई है ताकि बीमारी प्रारंभ होने से पहले ही उसकी जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने

आयुष्मान योजना का विस्तार करते हुए चिरायु योजना लागू की है, जिसके तहत एक लाख 80 हजार सालाना आय वाले 29 लाख परिवारों को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक के निशुल्क इलाज की सुविधा दी जायेगी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा में ईएसआई की गतिविधियों को गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पंचकूला के ईएसआई भवन की आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2018 में रखी थी और आज वर्ष 2023 में इस भवन ने कार्य करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईएसआई के प्रशासनिक भवन के निर्माण से उत्तर क्षेत्र में ईएसआईसी के पंजीकृत व्यक्तियों के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख बेहतर ढंग से हो सकेगी। उन्होंने प्रदेश में ईएसआई गतिविधियों को बेहतर ढंग से चलाने के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया।

राज्यपाल महोदय का बजट सत्र को लेकर संबोधन

(दिनांक 19.02.2023)

प्रभाव : माननीय राज्यपाल महोदय ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र 2023 के पहले दिन संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सुशासन से अंत्योदय के विजन को साकार कर रही है। एक लाख से कम वार्षिक आय वाले 3.35 लाख परिवारों की आय बढ़ाने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लागू किए गए कई नवाचारों से और मानव हस्तक्षेप कम करने से अनियमितताओं पर अंकुश लगा है और गुणवत्तापूरक सेवा प्रदायगी सुनिश्चित हुई है। डी.बी.टी. सुविधा, ऑटो अपील प्रणाली, परिवार पहचान पत्र योजना, स्वामित्व, मेरा पानी–मेरी विरासत, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान

योजना, आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम, जन सहायक एम–गवर्नेंस पहल, ई–खरीद, व्यवसाय सुधार कार्य योजना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम और कई अन्य पहलों ने सबका साथ–सबका विकास, सबका विश्वास–सबका प्रयास और हरियाणा एक–हरियाणवी एक की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं के लिए एक विशेष निगरानी प्रकोष्ठ बनाया है, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ–साथ मुख्य सचिव वर्तमान में 15 विभागों की कुल 58 हजार करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय की 91 परियोजनाओं की निगरानी करते है। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय ने हरियाणा की विशेष उपलब्धियों का जिक्र किया और सरकार के काम पर मोहर लगाई।

''पराली–एक पुंजी'' कुशल पराली प्रबंधन–समय की आवश्यकता' विषय पर कार्यशाला

(दिनांक 20.02.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज मोहाली में ''पराली–एक पुंजी '' कुशल पराली प्रबंधन–समय की आवश्यकता' विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया।

इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान , केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव सहित बड़ी संख्या में वैज्ञानिक भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा राज्य सरकार पराली जलाने की चुनौतियों को आर्थिक लाभ के अवसरों में बदलने की हर संभव कोशिश करेगी ताकि किसान को आर्थिक लाभ मिले और पर्यावरण भी स्वच्छ रहे ।

''पराली और पानी का प्रबंधन'' समय की मांग है। हरियाणा ने पराली जलाने के मामलों को कम करने के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं। हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में 40 फीसदी की

कमी आई है।

राज्य सरकार द्वारा किसानों को पराली –प्रबंधन पर कदम उठाते हुए पर पराली न जलाने पर 1000 रुपये प्रति एकड़ तथा 50 रुपए प्रति क्विंटल इंसेंटिव के रूप में दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए अनेक नए कार्यक्रमों को लागू किया है। पराली का उपयोग बायोमास बिजली परियोजनाओं, उद्योगों, कम्प्रेस बायोगैस संयंत्रों, कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्रों, ईंट भट्ठों, पैकेजिंग सामग्री, जैव ईंधन आदि में किया जाए ताकि पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि पराली को मशीनों और डीकंपोजर के माध्यम से अवशेषों में बदलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में उपयोग किया जा रहा है। पराली से किसानों की आय में बढ़ोतरी हो, यह भी हमें सुनिश्चित करना है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पानी के विवाद को आपसी सहयोग से सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा पहले ही दिल्ली को 250 क्यूसेक अतिरिक्त पानी उपलब्ध करवा रहा है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में ' मेरा पानी मेरी विरासत' योजना के माध्यम से सरकार फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे जल संरक्षण में काफी मदद मिली है और किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ हुआ है।

उन्होंने कहा कि पराली की गांठें बनाने के लिए किसानों को पराली प्रबंधन उपकरण पर प्रोत्साहन राशि और सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा, किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपकरणों पर 50 प्रतिशत अनुदान और कस्टम हायरिंग केंद्रों पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद

(दिनांक 22.02.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज विधानसभा बजट सत्र में माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा के उपरांत माननीय राज्यपाल महोदय जी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के द्वारा उठाए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष केवल विरोध करने के नाते से विरोध करता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता, वे ज्यादातर मुद्दे सिर्फ अखबारों में छपने के लिए ही उठाते हैं। उनके पास कहने के लिए कुछ नया नहीं है। ई–टेंडरिंग की व्यवस्था पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार को जीरो लेवल पर लाने के प्रयास किए हैं। पंचायतों और शहरी निकायों को अधिक अधिकार दिए हैं। विकास के कार्य पंचायतें करवाएंगी,

सरकार का काम फंड उपलब्ध करवाना है। हर पंचायत साल के शुरू में ही पोर्टल पर जो भी विकास कार्य किए जाने हैं, उनकी सूची अपलोड करेगी। सरकार ने इस वर्ष की आखिरी तिमाही में 1100 करोड़ रुपये पंचायतों को दिये हैं। काम की जरूरतों के अनुसार पंचायतें इस राशि को खर्च कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया है। अब तक पंचायतों में 2 लाख रुपये से नीचे के 2890 काम शुरू हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी बनाई है, जो समय–समय पर निर्माण कार्यों की चौकिंग करेगी और सर्टिफिकेट जारी करेगी।

इस सर्टिफिकेट के बाद ही पेमेंट की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संस्कृत अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए हाल ही में विज्ञापन जारी किया जा चुका है। 7471 टीजीटी पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें 714 संस्कृत टीजीटी के पद शामिल हैं। 1252 पद मेवात काडर के तथा 100 उर्दू टीजीटी पद भी शामिल हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्कूलों में एजुसेट चौकीदार को अब मल्टी पर्पज वर्कर कहा जाएगा और उन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत लाया जाएगा, जिससे उनका मासिक वेतन 7 हजार से बढ़कर लेवल–1 श्रेणी में न्यूनतम 14 हजार रुपये हो जाएगा।

खिलाड़ी कोटे के बारे में स्पष्ट करते हुए कहा कि ग्रुप–सी के कुल पदों का 3 प्रतिशत स्पोर्ट्र्स कोटे के तहत भरे जाएंगे। पुलिस, खेल, शिक्षा और बिजली विभागों में नियुक्तियों के साथ–साथ अन्य विभागों को भी जोड़ा जाएगा। प्रथम चरण में इन्हें अन्य विभागों में डेप्युटेशन पर भेजा जाएगा।

उन्होंने कहा कि फसल नुकसान की जानकारी का अधिकार स्वयं किसानों को देने के लिए फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है। किसानों द्वारा पहले पोर्टल पर जानकारी दर्ज करने का समय 72 घंटे था, जिसे अब बढ़ाकर 7 दिन कर

दिया है। इतना ही नहीं, किसान के साथ–साथ पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार भी इस पोर्टल पर खराब फसलों का ब्यौरा डालते हैं। इस डाटा को मेरी फसल–मेरा ब्योरा पोर्टल पर दर्ज फसलों के डाटा के साथ मिलान किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना लागू की है, जिससे लाल डोरा के अंदर की सभी संपत्तियों की रजिस्टरी सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश सरकार ने सबसे पहले लाल डोरा खत्म करने की पहल शुरू की थी। हमारी इस स्कीम का केंद्र सरकार ने भी समर्थन किया और आज देश के 8 राज्यों में स्वामित्व योजना लागू है।

स्कूली छात्रों से टेबलेट वापिस लेने के संबंध में कहा कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने के समय ही उन्हें टैबलेट स्कूल में वापिस जमा करवाना होगा। उन्होंने कहा कि हर साल सीईटी परीक्षा होगी, जिसके तहत ग्रुप सी व डी की भर्तियां की जाएगी। इसके लिए सरकार एक ही परीक्षा के आयोजन का विचार कर रही है। पेपर का स्टैंडर्ड 10वीं

कक्षा का होगा। हालांकि, ग्रप सी के लिए अलग से एक ओर पेपर देना होगा, जिसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस बारे में महाधिवक्ता से राय ली जा रही है।

उन्होंने कहा कि म्हारा गांव–जगमग गांव से पूरा प्रदेष बिजली से रौशन है। बिजली व्यवस्था में आमूलचूल सुधार हुए हैं। प्रदेश के 7255 गांवों में से 5694 गांवों यानी 78 प्रतिशत गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में स्टिलट पार्किंग के साथ 4 मंजिला घर बनाने की अनुमति दी गई थी, परंतु इस संबंध में कुछ शिकायतें आई हैं, जिसके बाद सरकार ने इस मामले में विशेष कमेटी का गठन किया है। कमेटी की रिपोर्ट आने तक कोई भी नया नक्शा पास नहीं होगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पीपीपी उनका डीम प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य मानवीय हस्तक्षेप को कम करके भ्रष्टाचार को बंद करना है। भ्रष्टाचार की लड़ाई भविष्य की लड़ाई है, इसलिए सब ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। सरकार ने 100 से अधिक पोर्टल बनाये हैं। डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में पैसे जा रहे हैं। 3 साल से जो अपात्र लाभार्थी थे, उनसे 1150 करोड़ रुपये की सरकार को बचत हुई है।

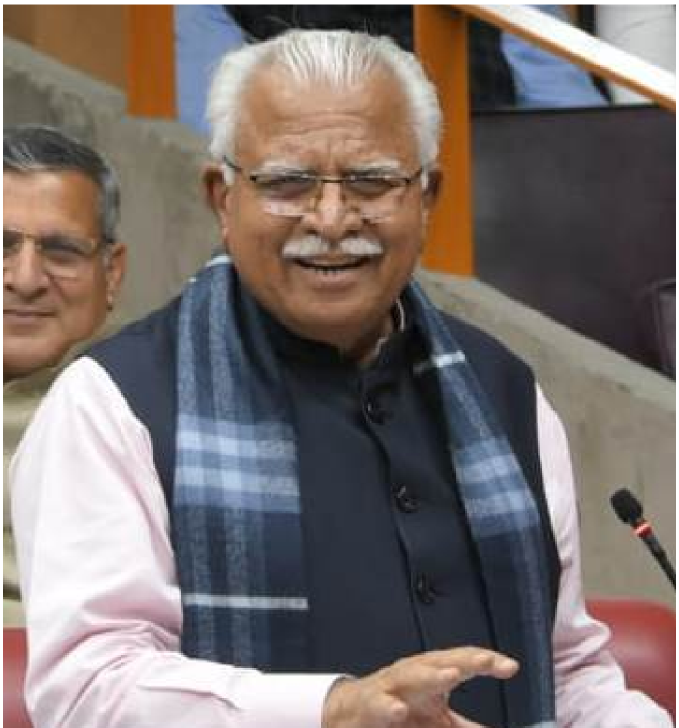

हरियाणा बजट 2023–24

(दिनांक 23.02.2023)

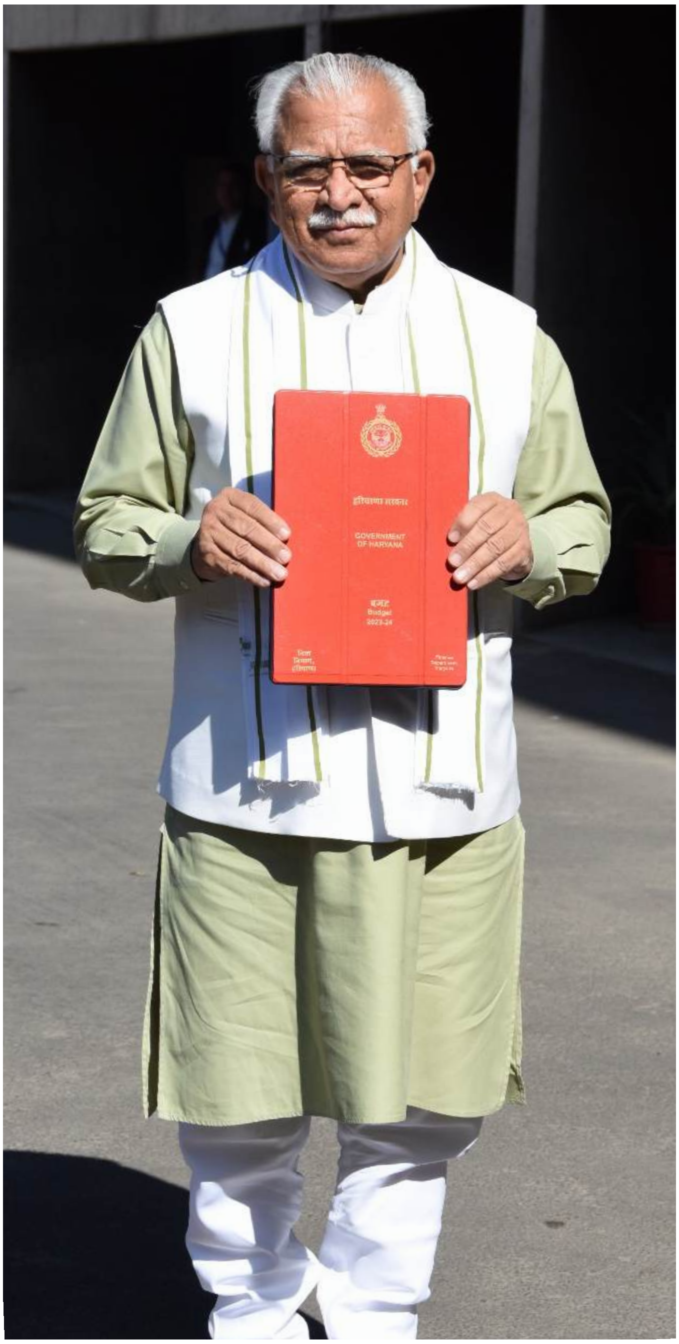

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में अमृत काल का हरियाणा का पहला बजट प्रस्तुत किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के नाते हरियाणा के इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा बजट पेश करते हुए वित्त वर्ष 2023–24 के लिए 1,83,950 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया और बजट में कोई नया कर भी नहीं लगाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में प्रदेश की जनता के लिए अनेक घोषणाएं कि जिसमें

बुजुर्गों की, पेंशन 2,750 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा

माननीय मुख्यमंत्री जी ने ने बजट प्रस्तुत करते हुए वृद्धावस्था पेंशन में 2,750 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की। साथ ही, उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन पात्रता आय 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख

रुपये करने की घोषणा की।

सरकारी आई.टी.आई. में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपये वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली हर लड़की को 2,500 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी।

अंत्योदय परिवारों को 2,000 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद

उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना, अंत्योदय परिवारों के लिए 1 लाख घर, चिरायु–आयुष्मान भारत योजना का लाभ 3 लाख रुपये वार्षिक तक आय वाले परिवारों को भी प्रदान करने, लैंड पूलिंग, लैंड पार्टनरशिप और ई–भूमि के माध्यम से 10 औद्योगिक सेक्टर और 10 शहरों में आवासीय सेक्टर को विकसित करने और नगरों में नवीनीकरण शुल्क के बकाया ब्याज राशि पर छूट योजना सहित कई नये आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि बजट सभी के लिए कल्याणकारी है। अब पत्रकारों को कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलेगी। चोटिल खिलाड़ियों के पोषण व पुर्नवास

के लिए राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र बनाये जाएंगे। आंगनवाड़ी वर्कर्स व चौकीदारों को भी चिरायु योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ–साथ प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। सब बच्चों को शिक्षा मिले, इसके लिए 6 से 18 वर्ष के हर बच्चे की मैपिंग की जाएगी।

सतत् विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुल बजट का 65.8 प्रतिशत आवंटित

'दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना की शुरूआत जिसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा की अंत्योदय उत्थान की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत परिवार पहचान पत्र डाटा के आधार पर 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के समय व्यक्ति की आयु के

आधार पर सहायता प्रदान करेगी। वित्त मंत्री जी ने बताया कि इस योजना के तहत 6 वर्ष की आयु तक 1 लाख रुपये, 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपये, 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक 3 लाख रुपये, 25 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष तक 5 लाख रुपये तथा 40 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक 2 लाख रुपये सहायता प्रस्तावित की गई है। इस लाभ में 18–40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी।

इसके साथ ही उन्होंने विशिष्ट विभागों को नागरिकों की देखभाल की जिम्मेदारी देने,हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास और आंतरिक लेखा परीक्षा को राज्य लेखापरीक्षा विभाग बनाने की भी घोषणा, पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए एक हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन शुरू करने, और प्रदेश में 4 अतिरिक्त पशु चिकित्सा पॉली –क्लिनिक बनाने की घोषणा भी की।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में 65000 नई ग्रुप C or D की भर्तियां निकालने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री जी ने कहा की यह हरियाणा के हर एक अंत्योदय परिवार का बजट है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

वन खेल कूद प्रतियोगिता

(दिनांक 25.02.2023)

प्रभाव : राज्य में जल्द ही 26वीं अखिल भारतीय वन खेल–कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास संत कबीर कुटीर पर 26वीं अखिल भारतीय वन खेल–कूद प्रतियोगिता का लोगो व शुभंकर जारी कर इन खेलों का आगाज कर दिया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा यह हमारे लिए गर्व की बात है कि 26वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा राज्य द्वारा किया जा रहा है।

इससे पहले भी दो बार क्रमशः वर्ष 2003 में 10वीं एवं वर्ष 2013 में 13वीं बार भी राज्य में इस प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है इस बार 10 से 14 मार्च तक इन

खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समस्त राज्यों, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, केन्द्र शासित प्रदेशों एवं वन अनुसंधानों के लगभग 2500 प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है । वन विभाग में ग्रुप सी में फॉरेस्ट गार्ड के पद पर खिलाड़ियों को नियुक्त कर अलग अलग खेल टीमें बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने खेलो के मस्कट का कृष नामकरण किया । लोगो एवम मस्कट का अवलोकन किया।

26वीं अखिल भारतीय वन खेल–कूद प्रतियोगिताओं का मुख्य केन्द्र पंचकूला के सेक्टर –3 स्थित ताऊ देवी लाल स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम में सभी प्रकार की दौड़ें इनडोर गेम्स जैसे कि बैडमिंटन, कैरम, टेबल टेनिस और चेस बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, वालीबॉल एवं रस्साकसी आयोजित होंगी।इसके आलावा, गोल्फ क्लब, सेक्टर –3 पंचकूला में गोल्फ तथा जिमखाना क्लब, सेक्टर –6 में लॉन टेनिस ब्रिज, स्नूकर, बिलियर्ड और

स्क्वैश प्रतियोगिताएं होंगी।

तीरंदाजी पंजाब विश्वविद्यालय के खेल –कूद मैदान में तथा शूटिंग प्रतियोगिता शूटिंग रेंज चण्डीगढ़ में होगी। भरोतोलन प्रतियोगिता राजकीय महाविद्यालय सेक्टर – 1 पंचकूला में आयोजित होगी।

मिकाडा के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद

(दिनांक 25.02.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिकाडा के लाभार्थियों से न केवल वर्चुअल संवाद किया बल्कि योजनाओं का फीडबैक भी लिया। अनेक लाभार्थियों ने सरकार की योजनाओं की प्रशंसा के साथ ही जल संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों को ड्रिप, मिनी–स्प्रिंकलर और पोर्टेबल–स्प्रिंकलर माईक्रो–इरीगेशन सिस्टम के लिए 58 हजार एकड़ खेतों के 19517 लाभार्थियों को 179.39 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जल सरंक्षण और उपलब्ध पानी का तर्कसंगत व मितव्ययिता से प्रयोग करने के लिए मिकाडा के माध्यम से विभिन्न स्कीमें चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हर बूंद–अधिक फसल की योजना शुरू की

है। इससे पानी के एक ही स्त्रोत से सिंचित क्षेत्र में काफी बढोतरी हो जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खेत में ही जलाशय के निर्माण पर सरकार व्यक्तिगत आवेदक के लिए 70 प्रतिशत की दर से और किसान समूहों के सदस्यों को 85 प्रतिशत की दर से सहायता प्रदान कर रही है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा में ड्रिप, मिनी –स्प्रिंकलर और पोर्टेबल स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई को बढाने व खेतों में वर्षा जल

संग्रहण के लिए तालाब बनाने व खालों को पक्का करने का कार्य मिकाडा को दिया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अटल भूजल योजना के तहत राज्य के 1656 गांवों में किसानों को उनके हिस्से की 15 प्रतिशत प्रतिपूर्ति राशि सीधे डीबीटी माध्यम से खातों में भेजी जा रही है। अब तक 11284 लाभार्थियों के खातें में 19 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में जिन किसानों ने सूक्ष्म सिंचाई को अपनाया है उनके खेतों में फल और सब्जियों की पैदावार में 52 प्रतिशत तक बढोतरी हुई है। इसके साथ ही खेत में ही जलाशय बनाने के लिए 2185 लाभार्थियों को 54.90 करोड़ रुपए और 2584 अन्य लाभार्थियों को 64 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाभार्थियों से कहा कि वे जल संरक्षण से जुड़ी इन योजनाओं का लाभ उठाएं और दूसरे किसानों को जल सरंक्षण के बारे जागरूक करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माइक्रो इरिगेशन का प्रयोग करने वाले किसानों को जल मित्र की संज्ञा दी।